झूठी लोकसभा और विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करें!

जनता की क्रांतिकारी राजनीतिक सत्ता की स्थापना करें!

नवजनवादी क्रांति को सफल बनाएं!

केंद्रीय कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

झूठी लोकसभा और विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करें!
जनता की क्रांतिकारी राजनीतिक सत्ता की स्थापना करें!
नवजनवादी क्रांति को सफल बनाएं!

प्रिय जनता!

चुनावों की नौटंकी जो 17वीं लोकसभा और आंध्रप्रदेश, ओड़िशा, सिक्किम और अरुणाचलप्रदेश के विधानसभाओं के लिए, अप्रैल–मई 2019 में और एक बार प्रदर्शित होनेवाली है। लेकिन हमारा देश में संसदीय जनवाद झूठी है। साम्राज्यवादियों के बीच जारी प्रतिस्पर्धा की व्यक्तीकारण के तौर पर और देश के दलाल नौकरशाही पूंजीपति और बड़े सामंत वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न राजनरीतिक पार्टियों (शासकीय गुटों) के बीच प्रतिस्पर्धा की व्यक्तीकरण के तौर होने वाली इन धोखेबाजी और कपटतापूर्ण चुनावों का मुख्य उद्देश्य इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि किस शासकीय गुट सत्ता में आना है और किस शासकीय गुट और पांच सालों तक साम्राज्यवादियों और देश के शोषक वर्गों के हित पूरा करने के लिए व्यापक जनसमुदायों पर अपनी क्रूर शासन जारी रखना है। इसीलिए मार्क्स और एंगेल्स ने स्पष्ट किए कि ''संसदीय रूप नकाब पहनी हुई बुर्जुआ वर्ग की तानाशाही ही है'' (मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन–सर्वहारा का अधिनायकत्व, पृष्ठ–430) और ''आधुनिक राज्य की कार्यपालिका पूरे बुर्जुआ वर्ग के सामान्य मामलों का संचालन करनेवाली समिति के अलावा और कुछ नहीं है'' (मार्क्स और एंगेल्स, कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र, पृष्ठ–33)।

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ भारतीय दलाल नौकरशाह बुर्जुआ और बड़े सामंत वर्गों द्वारा किए गए समझौते के अनुसार भारत की संसदीय नीति अमल में आयी थी, क्योंकि यहां बुर्जुआ जनवादी क्रांति सफल नहीं हुई है। 15 अगस्त, 1947 की आधीरात को 'आजाद का घोषणा' सिर्फ झूठा है। दरअसल उस दिन ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के प्रत्यक्ष औपनिवेशिक और अर्धसामंती व्यवस्था के स्थान पर नयीऔपनिवेशिक रूप के साम्राज्यवादी परोक्ष शासन, शोषण और नियंत्रण के तहत अर्धऔपनिवेशिक और अर्धसामंती व्यवस्था अस्थित्व में आयी है। यहां मौजूदा संसद जो 'विश्व के सबसे बड़ा जनतंत्र' के रूप में बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा है, वह सिर्फ दलाल नौकरशाह बुर्जुआ और बड़े

सामंत वर्गों का तानाशाह का प्रतिनिधित्व करती है, जो उनकी निरंकुश शासन पर पर्दा डालती है।

भारत आज एक नाम के वास्ते समप्रभुता वाली देश होने के बावजूद, साम्राज्यवाद देशों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एम.एन.सी.) और बहुअंतरदेशीय कंपनियों (टी.एन.सी.) के सामने झुके बिना, देश के राजनीकि, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर उनकी वर्चस्व कायम रखे बिना, किसी भी शोषक-शासक वर्ग के सरकार यहां टिके रहना नामुमकिन है। इसके साथ-साथ उन्हें जितना अधिकार व आजादी देते हुए, उनके हित पूरा करते हुए, उसके अंदर अपने हितों को पूरा करती हैं, ऐसी सरकारें उतना अच्छा नाम कमाती हैं। साम्राज्यवादी कार्पोरेट संस्थानों ने अपने हितों के अनुरूप काम करने वाली राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में खड़े होकर जनता को धोखा दे रही हैं।

नयी आर्थिक नीति का मतलब है, उदारीकरण्य, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर, वृद्धि दर बढ़ाने के नाम पर भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनरव्यवस्थीकृत करना। इसकी वजह से इस देश की बाजार विदेशी व्यापार पर निर्भर है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ आने वाली पूंजी की वजह से रोजगारविहीन विकास एक बड़ी समस्या बन गयी है। बेरोजगार बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। प्रदूषण बढ़कर पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। स्थानीय जनता की रोजी-रोटी नष्ट हो रहा है। पूंजी लगाना विश्व के आयात और सट्टे व्यापार पर निर्भर है। स्टॉक एक्सचेंजों की सूची अंतरराष्ट्रीय सट्टे व्यापारी के नियंत्रण में होती है। औद्योगिक और कृषि उत्पादों सहित सभी तरह के माल के दरें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्धारित होती हैं। पिछड़े देशों की मुद्रा की मूल्य डालर के आधार पर निर्धारित करने के वजह से, उसके तहत हमारा रूपये की मूल्य भी तेजी से गिर रही है। विदेशी पूंजी ने बैंकिंग, बीमा, रक्षा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी नियंत्रित करते हुए, पूरी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की गला घोट रही है। जनता को गरीबी की तरफ धकेलने वाली इस विदेशी पूंजी की भारी हमले के वजह से पुलिस और रक्षा क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर खर्च होकर जनता पर बोझ बढ़ रही है।

केंद्र में सत्ता में जो भी पार्टी हो (भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए हो, कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए हो, संशोधनवादी पार्टियों की गठजोड़ हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो), एक दूसरे से स्पर्धा लेते हुए भूमण्डलीकरण के 'सुधारों' को आक्रामकता से अमल कर रही हैं। विभिन्न राज्यों में सत्तासीन क्षेत्रीय पार्टियां भी विदेशी पूंजी

को आकर्षित करने के लिए इस होड़ में शामिल होकर साम्राज्यवादियों के लिए रियायत दे रही हैं। साम्राज्यवाद की सेवा करते हुए अपने हित हासिल करना नए ऊंचाइयों को छू रही है। एफडीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में हर क्षेत्र में घुस गयी है। मोदी की शासन में हाल ही में एफडीआई के लिए 100 प्रतिशत अनुमति मिली है। साम्राज्यवाद अर्थव्यवस्थाएं संकट में डुबे रहने के कारण वे और आक्रामकता से भारत जैसे पिछड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर अधिकाधिक वर्चस्व कायम के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में ही जो ग्लोबल कार्पोरेटों के लिए हमारा देश की अर्थव्यवस्था की दरवाजे पूरी तरह खोलने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, उन्हीं लोग प्रधान मंत्रियों, वित्त मंत्रियों, अर्थशास्त्रियों, कार्पोरेट वकीलों, बैंकरों, अफसरों के रूप में उद्भव हो रहे हैं। कानून सभाओं, केंद्र व राज्य सरकारों, सरकारी सशस्त्र बलों, न्यायालयों और प्रसारण साधनों के जरिए एलपीजी नीतियों और एलआईसी पॉलसी को संचालित करने में, जनता के अंदर बढ़ती असंतुष्ट और आक्रोश तथा इस सड़ीगली व्यवस्था के लिए विकल्प के रूप में माओवादी पार्टी के नेतृत्व अंकुरित होने वाली जनता की सच्ची क्रांतिकारी सत्ता को उखाड़ने के लिए 'ग्रीनहंट', 'समाधान' जैसे रणनीतिक हमलों को अंजाम देने में दक्षता रखने वाले ही चुनावों में जीत हासिल कर सकते हैं।

इसलिए हमने देश की वस्तुगत वास्तविकता को गहराई से समझाकर, आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों का बहिष्कार करने के लिए जनता को राजनीतिक रूप से चेतनाबद्ध व तैयार करना होगा। जनता को अपनी बुनियादी समस्याओं की हल के लिए जनांदोलनों और जनप्रतिरोध में गोलबंद करना होगा। उन्हें जनयुद्ध में शामिल कर यथासंभव सभी तरह के प्रयास करते हुए, जनता की सच्ची जनवादी राजसत्ता-क्रांतिकारी जन कमेटियों को चुनने और विस्तारित करने के लिए उन्हें संगठित करना होगा और उसमें सक्रिय रूप में शामिल होने लायक उन्हें तैयार करना होगा।

प्रिय जनता! 2014 में हुई संसदीय चुनावों में - कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए)-2 की सरकार पर जनता की असंतुष्ट, आक्रोश और विरोध का इस्तेमाल कर, साम्राज्यवादियों और देश-विदेशी कार्पोरेट अरबपतियों के बल पर, शब्दाडंबर के साथ, जनता के लिए कई वादों की झड़ी बहाकर जनता के अंदर भ्रम फैलानी वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) बड़ी बहुमत के साथ सत्तासीन हुई।

वर्तमान उसकी अवधि समाप्त होने के कारण जनता पर और एक बार चुनाव थोपे गये हैं। इस नेपथ्य में पांच साल की शासन में मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपनी चुनाव वादों को जिस हद तक पूरा कर पायी है, वह अपनी शासन में साम्राज्यवादीपरस्त, दलाल नौकरशाह बुर्जुआ और बड़े सामंत वर्ग अनुकूल जनविरोधी, देशद्रोही एलपीजी नीतियों और उसकी जनाकर्षक योजनाओं को जिस हद तक लागू की है, उससे देश और उत्पीड़ित जनता पर जितना गंभीर दुष्प्रभाव पड़ी है – उसकी पड़ताल करेंगे।

भाजपा ने साम्राज्यवाद का दासता करते हुए दलाल नौकरशाह बुर्जुआ, बड़े सामंत वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। वह साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) के आदेशों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए–2 द्वारा लागू नयी उदारवादी नीतियों को ही अनुसरण करते हुए उन नीतियों को और गति दी है। वह किसी भी चुनावी वादे को पूरा नहीं कर पायी, बल्कि जनता पर शोषण और उत्पीड़िन और तेज की है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण रूपये की मूल्य डालर के मुकाबले 73 रूपये तक पहुंच गयी है। औद्योगिक और कृषि संकट गंभीर स्तर तक पहुंच गयी है। तैयारी (मानुफैक्चरिंग) उद्योग रोज–रोज कमजोर हो रही हैं। देश की व्यापार घाटा बढ़ रही है। देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, आवासहीनता, बेरोजगार, अशिक्षा, साफ पेयजल की अभाव, अस्वस्थता बड़ें पैमाने पर बढ़ गयी हैं। इसके कारण लाखों की तादाद में लोग रोजी रोटी के लिए विदेशों, शहरों या दूसरे राज्यों में पलायन हो रहे हैं, जहां उन्होंने अकथनीय शोषण, उत्पीड़न और अत्याचारों का शिकार हैं या मानव तस्करी के जाल में विशेषकर दलित और आदिवासी युवतियां फंस रहे हैं। लोगों में भुखमरी और आत्महत्याएं बढ़ रही है। पहले, बीते चुनावों में मोदी द्वारा किए गए मुख्य वादे और उनकी शासन में लागू योजनाओं पर नजर डाले तो –

हर वर्ष दो करोड़ नौकरी देने की वादे के प्रति मोदी सरकार ने 'मेक इन इंडिया' के नाम से विदेशी पूंजी आने पर देश में उद्योग बढ़ेंगे, इससे आधुनीकरण और विकास होंगे, बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर पैदा होंगे, देश की जीडीपी वृद्धि दर 8 प्रतिशत तक होगी तथा बेरोजगार खत्म होंगी, के गलत प्रचार तेज किया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रिक्त पदों को भी उन्होंने भर्ति नहीं की। देश के अंदर रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल

इंटलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे नयी प्रौद्योगिकी (टेकनोलोजी) घुसने के कारण, इसकी प्रभव से भी नौकरी कम हुई हैं। ठेका मजदूर व्यवस्था और आउटसोर्सिंग में बढ़ोत्तरी हुई है। स्टार्ट अप, स्किल इंडिया, मुद्रा योजनाओं के कारण व्यवहार में कुछ भी अतिरिक्त रोजगार नहीं मिली है। 100 नयी स्मार्ट सिटियों का निर्माण अटक गयी है और उसकी जगह 100 शहरों को स्मार्ट बनाने तक आ गये हैं। ये सिर्फ अस्थायी तौर पर जनता में भ्रम फैलाने के बजाय रोजी-रोटी पैदा नहीं कर पायी हैं।

कालाधन - विदेशों में पड़ी हुई 500 बिलियन डालर कालाधन को बाहर निकालकर, देश में प्रति एक आदमी के बैंक खाते में 15 लाख रूपये जमा करने की वादा करने वाली मोदी सरकार वर्तमान इसके बारे में बात करना ही छोड़ देना एक बड़ा साजिश है। वीकीलीक्स, पनामा पेपर्स में उजागर हुए कुबेरों पर उन्होंने किसी तरह की कदम नहीं उठाया। दूसरी तरफ कालाधन पर अंकुश लगाने के नाम पर नोटबंदी कर चोरी-चुपके देश के कुबेरों और कार्पोरेटों घरानों के पास मौजूद कालाधन को सफेदधन के रूप में बदल कर उन्हें फायदा पहुंचायी है और आम आदमी की रीड तोड़ दी है। फलतः जीडीपी की वृद्धि 1 प्रतिशत कम हुई। 15 लाख नौकरियां चले गए। 3 लाख छोटे व मध्यम उद्योग बंद हो गए। नयी नोट छपने के लिए हजारों करोड़ रूपये खर्च हुई। मोदी सरकार बड़े पैमाने पर वस्तु सेवा कर (जीएसटी) लगाने द्वारा जनता पर टैक्स आतंक फैलाकर बड़ा आर्थिक बोझ थोप दिया है। इससे छोटे और मध्यम पेशों और व्यापारों की कमर तोड़ दी और उनको नुकसान हो गए। नोट बंदी, जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) छिन्नभिन्न हो जाने और रोजगार योजना-नरेगा के लिए पैसे कम करने के कारण 2 करोड़ नौकरियां चले गए।

किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य - किसानों के फसलों के लिए उनकी लागत से 50 प्रतिशत लाभ के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की अपनी वादे को मोदी सरकार ने कूड़ेदान में डाल दिया है और बैंकों के हजारों करोड़ रूपये लूटने वाले ललित मोदी, मेहुल चौक्सी, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों को सुरक्षित देश से बाहर भेज दिया है। हर एक बजट में कार्पोरेट कंपनियों के लिए लाखों करोड़ रूपये टैक्स रियायत (आर्थिक वर्ष 2015-16 और 2016-17 में ही 12 लाख करोड़ रूपये) दे रही है। उन कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए एक लाख 32 हजार करोड़ रुपयों का कर्ज माफ कर दी है। लेकिन मोदी सरकार कर्ज से दबकर बड़े पैमाने पर

आत्महत्याएं करने वाले किसानों को राहत के रूप में एक पैसा भी कर्ज माफ नहीं किया।

गंगा नदी अभी भी प्रदूशित है - पर्यावरण के बचाव के बारे में बेइमानी मोदी सरकार ने गंगा नदी को साफ करने की अपनी चुनावी वादे को पूरा करने के नाम पर 'नमामी गंगे' योजना को एक जनाकर्षक योजना के रूप में और कार्पोरेटों के जेब भरने की योजना के रूप में तब्दील कर दिया है।

बढ़ती कर्ज - मोदी के शासन में देश साल दर साल कर्ज की दलदले में फंसती गयी है। 2018-19 की केंद्रीय बजट के अनुसार देश की कुल कर्ज लगभग 90 लाख करोड़ रूपये तक पहुंच गयी। यानी अभी जन्म शिशु के सिर पर भी लगभग 75 हजार रूपयों के कर्ज है। इससे वायदे और सूद के लिए हर साल बजट में एक चौथाई खर्च हो रही है। बाकी बजट खर्च के लिए पर्याप्त नहीं होने और साम्राज्यवादी संस्थानों के शर्तों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में विनिवेशीकरण (निजीकारण) कर साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देश के कार्पोरेटों के लिए बेचना, महत्वपूर्ण रक्षा क्षेत्र में भी 100 प्रतिशत विदेशी निवेश के लिए अनुमति देना, संपन्नों पर कर कम करना और गरीबों पर बढ़ाना, कल्याणकारी योजनाओं पर कटौती कर बजट में खर्च कम करना, नये कर्ज के लिए ढूंढना आदि मोदी सरकार द्वारा लागू एलपीजी नीतियों का ही नतीजा है। यह राष्ट्रीयता और स्वदेशी नारों से गूंज उठाने वाली भाजपा और आरएसएस के साम्राज्यवाद अनुकूल असली चहरे को उजागर कर रही है।

कल्याणकारी कार्यक्रम - मोदी सरकार ने यूपीए-2 की शासन में शुरू की गयी योजनाओं का ही नाम बदल कर, उन्हें अपनी योजनाओं के रूप में तोड़-मरोड़कर पेश करने वाली कार्पोरेट मीड़िया प्रचार से जनता को भ्रम में डालने के लिए उन्होंने गंभीर प्रयास किया। वह जनकल्याण के लिए चुनावों में किए गए सभी वादों को कूड़ेदान में डालते हुए सिर्फ इन योजनाओं की प्रचार के लिए ही 5,246 करोड़ रूपये खर्च की। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, साफ-सफायी जैसे सामाजिक सेवाओं पर, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, अंत्योदय आदि जनकल्याणकारी योजनाओं पर सरकारी खर्च को रोज-रोज कम कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को निजीकरण की है। इसी बीच उनके द्वारा शुरू की गयी आयुष्मान भारत योजना के मुताबिक हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रूपये के स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त मिलने का दावा झूठ है। यह योजना इस तरह साबित हो रही है कि कार्पोरेट अस्पतालों के लिए भारी मुनाफें पहुंचाने वाली योजना के सिवा और

कुछ नहीं है। सभी के लिए आवास की योजना कुछ लोगों की आंसूपोंछ तक ही सीमित रह गयी है। जनधन योजना के जरिए जमा किए गए 70 हजार करोड़ रूपयों के छोटे रकम से कार्पोरेटों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के बजाय जनता के हित नाममात्र ही है। ठीक उसी समय में क्रांतिकारी, जनवादी और राष्ट्रीय-मुक्त आंदोलनों को कुचलने के लिए सरकार के पास पैसों के लिए कोई कमी नहीं है। यह सरकार गलत आंकड़ों से बड़े सफलताएं हासिल करने का दावा कर रही है। कई योजनाओं की छोटी-सी सफलता को बढ़-चढ़ कर पेश कर रही है। उदाहरण के लिए प्रधान रूप से गैस कंपनियों के हितों और वोट बैंक बढ़ाने के लिए शुरू की गयी उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन जिन बीपीएल परिवारों के लिए मंजूर की गयी है, उन्हें खाली हुयी गैस सिलेंडरों का भी भरने की आर्थिक स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ गैस दर आसमान छू रही है। लेकिन मोदी सरकार इसे सफल योजना कहते हुए ढिंढोरा पीट रही है। लोग खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि मोदी सरकार सामान्य लोगों के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं होने वाली, फायदा नहीं होने वाली, सिर्फ देश-विदेशी कार्पोरेटों के हितों के लिए उपयोगी होने वाली बुलेट ट्रेन योजना, डिजिटल इंडिया, एक्सप्रेस वे, अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे जैसे परियोजनाओं को लागू कर अपनी शोषक वर्ग की चरित्र को उजागर कर रही है।

बढ़ती महंगाई - अंतरराष्ट्रीय बाजार में साम्राज्यवादियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण कच्चे तेल की दरें कम होने के बावजूद, देश में मोदी की शासन में पेट्रोल और डीजिल दरें, रोजमर्रा की जरूरत चीजों की दरें रिकार्ड तोड़ रही हैं। दरों को नियंत्रित करने की उसकी चुनावी वादे शुष्क वादे हो गयी हैं।

संवैधानिक स्वतंत्र संस्थानों की कब्जा - 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' कहने वाले मोदी ने समस्त अधिकारों को अपने हाथों, अपने आरएसएस और उसकी वफादार सेवकों के हाथों में रखा है। रक्षा, गृह, विदेश और आर्थिक क्षेत्र सहित नीति आयोग और रिजर्व बैंक के सभी गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोबल द्वारा अपने हाथों से चला रहे हैं। मोदी-शाह-भागवत गुट ने सत्ता और भ्रष्टाचार को केंद्रीकृत किया है। देश के हितों और नाममात्र जनवाद का भी नजरअंदाज कर देश में ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद की स्थापना की है। इन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों, शोध संस्थानों का भगवाकरण करते हुए वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के रूप में हिंदुत्व दकियानूसियों को नियुक्त किये

हैं। शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। न्याय व्यवस्था, सीबीआई, आरबीआई, चुनाव आयोग आदि सभी संवैधानिक स्वतंत्र व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप कर, उन्हें कब्जा करने की कई कोशिशें भी किये हैं। नोटबंदी के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा लिए जाने वाले निर्णय सरकार करती रही थी। सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने मजबूरन जनता के सामने आकर कहना पड़ा कि 'जनवाद' खतरे में है।

भ्रष्टाचार - 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' के तर्ज पर भ्रष्टाचारविहीन सरकार देने की लफ्फाजा करने वाले मोदी ने कई भ्रष्टचार घोटाले में फंस गये हैं। नितिन गडकरी के पुर्ति घोटाला, किरिन रिजिजु के 450 करोड़ रूपये वाली पॉवर प्लांट घोटाला, अमित शाह के बेटा जय शाह संपत्ति 10 गुणा बढ़ जाना, गुजरात में टाटा नानो कंपनी की स्थापना के लिए मोदी के लिए मिली 30 करोड़ रुपयों के रकम, गौतम अदानी के सात बिलियन डालर के खदान लीज घोटाला, उनकी कंपनी के लिए एक बिलियन डालर वाली कर्ज घोटाला, उनके लिए 45 हजार करोड़ रूपये मुनाफा पहुंचाने में मददगार साबित हुई गुजरात तट के भूमि लीज घोटाला, दाल्मिया ग्रुप के लिए लालकिला लीज घोटाला, मोदी की शासन के दौरान ही 8,748 बैंक घोटाले होना, देश की इतिहास में सबसे बड़े 58,000 करोड़ रूपयों के राफेल युद्ध विमानों का घोटाला उजागर होना आदि ने मोदी की भ्रष्टाचार शासन के लिए कुछ उदाहरण मात्र हैं।

गरीबी - पांच साल की मोदी की नीतियों के कारण देश में अमीर और गरीबों के बीच अंतर, दलाल नौकरशाह बुर्जुआ और बड़े सामंतों की संपदा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। देश की आबादी में एक प्रतिशत कुबेरों के पास देश की 73 प्रतिशत संपदा है, जबकि निचले स्तर के बाकी 99 प्रतिशत लोगों के पास मौजूदा संपदा सिर्फ 27 प्रतिशत ही है। मात्र एक प्रतिशत रही कुबेरों ने अपनी संपदा को 2017 तक 21 लाख करोड़ रूपये तक बढ़ाये हैं, जबकि 50 प्रतिशत गरीबों के पास कुछ भी संपदा नहीं रह गयी। देश के 49 करोड़ जनता रोज 20 रूपये भी खर्च करने में और न्यूनतम जरूरतों का भी पूरी करने में असमर्थ होकर आधेपेट गरीबीरेखा से नीचे जीने में मजबूर हैं। देश के करोड़ों जनता के पास पेयजल की सुविधा नहीं है। हजारों गांवों के लिए बिजली की सुविधा नहीं है। पौष्टिक आहार की अभाव से एक तिहाई शिशुवों के वजन कम होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दरअसल मोदी सरकार कार्पोरेट घरानों के हितों को पूरा करते हुए उनके लिए 'अच्छे दिन' लायी है।

साम्राज्यवाद और सामंती संस्कृति के विलयन - देश में सत्तासीन हिंदू

फासीवादी गुट ने सतह पर साम्राज्यवाद संस्कृति के खिलाफ दिखाई देता है, लेकिन वह साम्राज्यवाद संस्कृति के साथ सनातन हिंदुत्व वाली सामंती संस्कृति को मिलाकर अमल कर रही है। सभी भारतीय हिंदू हैं के भावना को बड़े पैमाने पर प्रचारित कर रहे हैं। हिंदूबहुल समाज में हिंदुओं की भावनों पर किसी को परवाह नहीं है, कहते हुए लोगों को भड़का रहे हैं। गोमांस खाना भारतीय परंपरा से अलग नहीं है, यह जानने के बावजूद, सिर्फ हिंदू धर्मोन्माद और झूठी राष्ट्रवाद को भड़काने के लिए गोमांस विरोधी सांस्कृतिक आक्रामक अभियान को बड़े पैमाने पर जारी रखे हुए हैं। लोग क्या खाना है, क्या ओढ़ना है, क्या बात करना है, क्या लिखना है, क्या सोचना है, क्या करना है, इसके आदेश दे रहे हैं। इसके खिलाफ कोई भी बात या काम करने से उन्हें राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही घोषित कर रहे हैं। निरंकुश तरीके से शहरों में गरीबों की बस्तियों को ध्वस्त कर कुंभमेलाओं का आयोजित कर रहे हैं। कश्मीर और उत्तर-पूर्व आदि उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के जनता पर हमले तेज किए हैं। अयोध्या में रामजन्म भूमि समस्या को कभी नहीं बुझाने वाली आग की तरह सुलगा रहे हैं। मस्जिद और चर्चों को ध्वस्त कर मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। युवक-युवतियों को निष्क्रिय करने के लिए मादक पदार्थ इस्तेमाल करने की संस्कृति को बड़े पैमाने पर व्याप्त कर रहे हैं। पब-मल्टीप्लक्स की संस्कृति की खुलेआम अनुमति देते हुए ही, जीन्स पहनने वाली युवतियों को तीव्र रूप से अपमानित कर रहे हैं। अंतर-धर्म और अंतर-जातीय विवाह करने वाले जोड़ों पर 'लव जिहादी' की ठप्पा लगाकर 'इज्जत' के नाम पर हत्या कर रहे हैं। नेताओं के पैर धोने के लिए मजबूर कर रहे हैं। गोरक्षा के नाम पर मुस्लिम और दलितों को हत्या करने वालों का सम्मानित करते हुए, भीड़ की हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये साम्राज्यवाद और सामंतवाद संस्कृति की विलयन को दर्शाने वाली सिर्फ कुछ रूझान ही हैं। इस ब्राह्मणवादी हिंदू धर्मोन्माद मूढों ने आधुनिक विज्ञानशास्त्रों का धज्जियां उड़ाते हुए देश में सनातन काल में ही मोटार कार, विमान और प्लास्टिक सर्जेरी की खोज होने की काल्पनिक पुराणों की कहानियां रटते हुए झूठी विज्ञान को आगे ला रहे हैं। 'गीता' को राष्ट्रीय ग्रंथ की हौसियत देकर देश को 'हिंदू राज्य' के रूप में बदलना चाहते हैं। 1947 की देश की विभाजन के संदर्भ में हुई हत्याकांड, 1984 की सिक्कों के हत्याकांड, 1987 की हशिमपुरा हत्याकांड, 2002 की बाबरी मस्जिद की विध्वंस, 2002 की गुजरात हत्याकांड, 2013 की उत्तरप्रदेश में ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादियों द्वारा अंजाम दिए गए हत्याकांड आदि

की इस हिंदू फासीवादी गुट ने सांस्कृतिक वारिश तौर पर खड़े होकर मध्ययुगीन के चाणक्य नीति को लागू कर रही है।

ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद - मोदी–अमित शाह–मोहन भागवत के नेतृत्व वाली हिंदू फासीवादी गुट ने साम्राज्यवाद के वित्तीय पूंजी के हितों को बचाने के लक्ष्य से समाज को धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के रूप में आपत्काल जैसी परिस्थिति को पैदा कर रही है। फलतः आरएसएस के नेतृत्व वाली संघ परिवार शक्तियों ने देशभर में मनमानी हिंसाकांड करने में तुली हुई हैं। गोमांस के नाम पर दलितों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हो गयी है। गरीबों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को जीना ही दूभर हो गयी है। निर्दोष लागों को जान से मारना, पीट–पीट कर मारना बढ़ गयी है। हिंदू फासीवादियों ने 'विभाजन करो–राज करो' के साथ 'भड़कावो–राज करो' के नीति को जोड़कर अमल कर रहे हैं। आरक्षण के खिलाफ षड़यंत्रकारी तरीके से एससी, एसटी और ओबीसीयों में फूट डाल रहे हैं। पेश्वायी विरोधी युद्ध में अपने प्राण न्योछावर करने वाले भीमा कोरेगांव के अमर शहीदों के याद में 200वीं वर्ष की स्मृति दिवस के अवसर पर भीमा कोरेगांव में 200 से अधिक दलित, जनवादी, सामाजिक संगठनों के बैनर तले हुई जनप्रदर्शन में तीन लाख लोग जमा हो जाने, उनके द्वारा नयी पेश्वायी, नहीं चलेगा' के नारे देना बर्दास्त नहीं करने वाली हिंदू फासीवादी तत्वों ने राज्य के बल पर पाशविक रूप से हमले किए हैं। इसका एक दिन पहले पुणे में आयोजित एल्गार परिषद की सभा में मोदी की हत्या करने की साजिश का बहाना बनाकर देशभर में दलित, जनवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर मोदी के भाड़े की पुलिस बलों द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए, उनपर अवैध रूप से 'उपा' जैसे क्रूर कानूनों को लगाकर जेलों में ठूंसकर, देश में आतंक मचाया। दूसरी तरफ भीमा कोरेगांव दंगों का नेतृत्व करने वाली असली अपराधियों और संघ परिवार संगठनों के नेता शंभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे स्वेच्छा से घूम रहे हैं। अपने हिंदू फासीवाद की मूर्तरूप, देश को लौहे के पैरों से रौंदकर तेलंगाना सशस्त्र किसान आंदोलन जैसे कई संघर्षों में खून बहाने वाले, अकथनीय अत्याचार करने वाले, हजारों कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों और राष्ट्रीयमुक्ति संघर्ष के योद्धाओं का हत्यारा, देश में पुलिस राज और राष्ट्रीयताओं पर दमन का मूर्तरूप और देश की विभाजन के संदर्भ में हिंदू–मुस्लिमों के बीच कभी बुझा नहीं पाने वाली आग सुलगाने वाले विनाशकारी नेताओं में से एक सरदार

वल्लभभाई पटेल की 185 मीटर लंबाई मूर्ति को मोदी सरकार ने अपनी बजट में 200 करोड़ रूपये आबंटित कर निर्माण किया। इसे 'एकता मूर्ति' नाम देकर, नोटबंदी और जीएसटी पर तथा देश को देश-विदेश कार्पोरेटों का कौड़ियों में बेचने पर लिए गए नर्णय पटेल द्वारा लिए गए साहसिक कार्रवाइयों से तुलना करते हुए, राष्ट्रीय उन्माद को भड़का रही है।

मोदी राज में गरीबों के लिए काम करना अपराध हो गयी है। नौकरी मांगने पर बेरोजगारों को, जायज दर मांग ने पर किसानों को, मुफ्त शिक्षा मांगने पर छात्रों को, समानता पर बात करने से महिलाओं को, जातिगत ज्यादती पर सवाल खड़े करने पर दलितों को - इस तरह सभी वर्गों के हजारों लोगों को सरकार ने जेलों में ठूंस रह रही है। छात्र, युवा, महिला, मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर क्रूर दमन प्रयोग करते हुए, कानून, न्याय और मानवता का नजरअंदाज कर रही है। वह "मुकाबला करने वाले का गला घोट दो" के तर्ज पर फासीवादी राज अमल कर रही है। कलबुर्गी, गोविंद पन्सरे, नरेंद्र धबोल्कर, गौरी लंकेश जैसे तर्कणावादियों और जनवादीप्रेमियों को मार रही है और मारने की धमकियां दे रही है। जीने की अधिकार को छीन रही है। उसकी भगवा आतंकी नेटवर्क की पर्दाफाश हो जाने, उसकी गुप्त स्थान, हीट लिस्ट (ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनकी हत्या की जानी है), हत्या की योजनाएं, हथियार, गोलाबारूद और बम मिलने के साथ-साथ उसकी सारे षड़यंत्र भण्डाफोड़ हो गयी हैं। ये तो जगजागिर है कि इसके लिए सरकार और पुलिस की सहयोग है। भाजपा-आरएसएस गुट ने सबरीमला के अयैप्पा मंदिर में महिलाओं की प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट की फैसले के बारे में अवसरवाद की रूख अपनायी है। उसके नेतृत्व में वहां काले कपड़े पहने हुए हिंदू फासीवादी तत्व गुण्डागर्दी चलायी है। महिलाओं से छुआ-छूत बरती गयी है। केरलम में उत्पन्न 'मानव निर्मित' भारी प्रकृतिक त्रासदी से जनता की ध्यान भटकाने की काम किया है। भारी विनाश से जूझ रहे उस राज्य को देश-विदेशों से मदद से वंचित रखकर जनता को असहाय छोड़ दिया है।

मोदी की शासन में देशभर में मनमानी आदिवासियों, किसानों, दलितों की जमीन जब्त कर कार्पोरेट कंपनियों को दे देना, निरंकुश तरीके से उन्हें अपने गांवों, बस्तियों, अपने पारंपरिक जमीनों व घरों से विस्थापित करना बेहिसाब बढ़ गयी है। 5वीं अनुसूची अमल आदिवासी इलाकों में जल-जंगल-जमीन पर आदिवासियों की अधिकार को कुचलते हुए साढ़े पांच लाख की तादाद में

सरकारी की भाड़े की सशस्त्र बलों की तैनात कर, क्रूर दमन प्रयोग करते हुए, देश-विदेशी कार्पोरेट कंपनियों के कई खनन परियोजनाओं, भारी प्राजेक्टों को शुरू करने और अभयारण्यों की स्थापित करने के लिए तैयार हुई है। प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए रूकावट के रूप में मौजूद हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आंदोलन को उखाड़ने के नाम पर वह नाजायज 'जनता पर युद्ध' तेज किया है। संविधान, कानून, कोर्ट आदेशों का भी उल्लंघन करते हुए रणनीतिक 'ऑपरेशन ग्रीनहंट', उसके बाद 'समाधन' हमले के जरिए फर्जी मुठभेड़ों, दर्जनों जनसंहारों द्वारा सफेद आंतक पैदा किया। इसमें लगभग 420 क्रांतिकारियों और 360 जनता (इसमें 215 महिलाएं भी शामिल है) की हत्या की। कई गांवों और सैकड़ों घरों को आग लगाकर, 'उपा' जैसे क्रूर कानूनों के अंदर हजारों लोगों को जेल में ठूंस दी। एक सौ से ज्यादा आदिवासी युवतियों पर अत्याचार का शिकार हुई, उनमें से कइयों को हत्या की गयी। हजारों जनता को क्रूर यातनाएं दी गयी। इस दमन के बारे में सच्चाई को सामने लाने के लिए प्रयासरत पत्रकारों, लेखकों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला, आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ कई संसदीय पार्टियों को भी धमकियां देना; छत्तीसगढ़ में 'अग्नि' जैसे प्रतिक्रांतिकारी संगठनों द्वारा उन्हें अपमानित करना और मारने की धमकियां देना; बिहार-झारखण्ड में पीएलएफआई, टीपीसी जैसे सशस्त्र हत्यारा गुटों के जरिए हमारे गुरिल्ला दस्तों और स्थानीय जनसंगठनों के कार्यकर्ताओं पर क्रूर हमले कर हत्या करना और उनकी संपत्ति को जब्त करना जारी है। आंदोलन के इलाकों के अंदर और बाहर मैदान और शहरी इलाकों में खुले-कानूनी जनांदोलनों पर भी तीव्र दमन आम बात बन गयी है। कोर्ट बता रहे हैं कि माओवादी पार्टी सदस्य होना अपराध नहीं है, इसके बावजूद कई जनवादी, दलित और सामाजिक कार्यकर्ताओं को 'शहरी माओवादी' के नाम पर षड़यंत्र मामले में फंसा दिया है। झूठी सुनवाई प्रहसन चलाकर लंबे समय की सजाएं, आजीवन कारावास और फांसी की सजाएं भी दी गयी। आंदोलन के इलाकों में सरकार के भाड़े की बलों के अत्याचार बेरोकटोक जारी है। वहां किसी भी तरह के मानवाधिकार नहीं रह गयी है। सरकारी बलों के अत्याचारों पर, विशेषकर आदिवासी महिलाओं पर हुई यौन अत्याचारों पर और संपत्ति की विध्वंस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्टों का भी नजरअंदाज किया गया।

भाजपा ने कानूनों को नजरअंदाज कर, सरकार की सभी अधिकारों को

दुरुपयोग कर 10 करोड़ की पार्टी सदस्यता हासिल करने की दावे के साथ घमण्ड से चिल्ला रही है। बीते चार सालों में सभी पार्टियों के लिए 637.54 करोड़ रूपये चंदे मिली थी, उसमें सिर्फ भाजपा ने ही 488.94 करोड़ हासिल की। वह अनधिकारिक रूप से हजारों करोड़ रूपये इकट्टा कर देश में सबसे अमीर पार्टी हो गयी है। इसमें अधिक हिस्सा देश के कार्पोरेट कुबेरों से ही आयी हुई है। इसलिए इन संसदीय पार्टियों में से जो कोई भी पार्टी, सत्ता में आयी या नहीं आयी, इन कुबेरों की हितों का ही पूरा करने के लिए विश्वास के साथ काम करती है। उनके लिए जनता के हित परहेज नहीं है।

इस तरह देश की संपदा और संसाधनों की बेरोकटोक, लगातार कार्पोरेट कंपनियों की लूट, 75वीं स्वतंत्र वर्षगांठ तक, यानी 2022 तक ब्राह्मणीय हिंदू राज–'नया भारत' का निर्माण, क्रांतिकारी, जनवादी और राष्ट्रीय–मुक्ति आंदोलनों पर बढ़ती फासीवादी दमन, विशेषकर, क्रांतिकारी आंदोलन का सफाया करने के लिए प्रतिक्रांतिकारी फासीवादी दमन रणनीति–'समाधान' का क्रूरता से अमल करना आदि आज की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की असली चहरा को दर्शाता है। इसे जनता के बीच राजनीतिक रूप से भण्डाफोड़ करना बहुत ही आवश्यक है।

विभिन्न उत्पीड़ित वर्गों और सामाजिक तबकों पर पांच साल की मोदी शासन का प्रभाव

मजदूरों पर – मोदी सरकार देश–विदेशी कार्पोरेट कंपनियों के हितों को पूरा करने के लिए, मजदूरों द्वारा दशकों साल से लड़कर हासिल किए गए, उनके लिए अनुकूल रहे कई श्रम कानूनों में संशोधन करने व रद्द करने के साथ–साथ कई मजदूर विरोधी कानून लाकर उन्हें पीछे 19वीं सदी में वापस ले गयी है। फलतः कई कंपनियों के मालिकानों ने अपनी मनमानी से मजदूरों को अपनी कंपनियों से निकाल दिए। स्वेच्छा से सेवानिवृति के नाम पर लाखों मजदूरों को सरकारी और निजी क्षेत्रों के कंपनियों से निकाल दिए। मजदूरों और कर्मचारियों के वेतनों पर बड़े पैमाने पर हमला किए। उन्हें मिलनेवाली बोनस राशि और डी.ए. (अंतिरिम राशि) को रोक दिए। कर्मचारियों, शिक्षकों और सेवकों के महीनेंभर वेतनों को रोककर रखा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की परिस्थिति और दूभर हो गयी, वे हर साल न्यूनतम एक लाख की तादाद में मर रहे हैं। संगठित क्षेत्र से लाखों की संख्या में छंटनी के कारण असंगठित क्षेत्र की संख्या बढ़ रही

है। महंगाई में वृद्धि के कारण श्रमिक वर्गों की जीवनस्तर तेजी से गिर रही है।

किसानों पर - मोदी सरकार द्वारा लागू किसान-विरोधी, कार्पोरेट-परस्त कृषि नीतियों के वजह से कृषि संकट तेज हो गयी। इसके कारण खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों के दरें आसमान छूना, किसानों के लिए दी जाने वाली सब्सिडियों समाप्त करना या कम करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खोखला साबित हो जाना, अकाल के लिए सहयोग की सिर्फ लफ्फाजी साबित हो जाना, सिंचाई योजनाओं के प्रति घोर लापरवाही आदि किसान विरोधी नीतियों और योजनाओं के परिणामस्वरूप किसानों पर कर्ज की बोझ बढ़ गयी है। उनपर सूदखोरों की लूट तेज हो गयी है। फसलों के लिए समर्थन मूल्य नहीं है। ग्रामीण बेरोजगारी में बहुत वृद्धि हुई है। फसल बीमा के नाम पर किसानों के जेब काटकर बीमा कंपनियां लूटने की सिलसिला जारी है। इससे रूई, गन्ना, मिर्च, प्याज, चाय, नारियाल उगाने वाले 50 हजार से अधिक किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। कार्पोरेट कृषि विस्तारित हो रही है। भूमिहीन, गरीब/जमीन खो जाने वाले किसानों की जिंदगी अत्यंत गरीबी से दूभर हो जाने की वजह से करोड़ों की तादाद में रोजी-रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं।

शहरी मध्यम वर्ग पर - हर परिवार में बेरोजगार युवक-युवतियां होते हैं। छोटे-छोटे व्यापार करने के लिए प्रयास कर नुकसान झेल रहे हैं। बढ़ती महंगाई, अधिक टैक्स के साथ तुलना करें तो, मध्यम वर्ग के लोगों की आय कम होकर जीवन दूभर हो रही है। इन्होंने सट्टा बाजार के पतन, बैंक घोटाले और चिटफंड घोटाले आदि के कारण अपनी निवेश नुकसान हो गयी हैं। इनपर नोटबंदी और जीएसटी का प्रभाव अधिक है।

देशीय बुर्जुआ वर्ग पर - विदेशी वित्तीय पूंजी और विदेशी माल के हमले तीव्रता रोज-रोज बढ़ने, मोदी की शासन में नयी उदारवाद नीतियां तेजी से लागू की जाने के कारण छोटे और मध्यम क्षेत्र में देशीय बुर्जुआ वर्ग गंभीर नुकसान झेल रहे हैं।

विभिन्न सामाजिक तबकों पर -

महिलाओं पर - वर्ग समाज की शुरूआत से लेकर द्वितीय स्थान में रही महिलाओं की स्थिति मोदी की शासन में और बिगड़ गयी है। गिरती रोजगार अवसर और बड़े पैमाने पर छंटनी के कारण महिलाएं फिर से परिवारों (घर में) तक सीमित होने में मजबूर हैं। सामाजिक संबंध घटकर सामंती सोच मजबूत हुई

है। परिवार में अधिक बोझ महिलाओं पर पड़ रही है। ब्राह्मणवादी हिंदू विचारधारा ने साम्राज्यवाद संस्कृति के साथ सामंती मूल्यों और पितृसत्तात्मक सोच (मनुधर्म) को मिला दी और मजबूत की। मोदी की शासन में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के नारा सिर्फ नारा तक ही सीमित रह गयी। महिलाओं पर अत्याचारों और हत्याओं में 61 प्रतिशत और नाबालिग बच्चियों पर 133 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं। कई जगहों पर कन्याश्रम वेश्या गृहों के रूप में, विश्वविद्यालयों में महिला आश्रमों को 'पिजरों' के रूप में तब्दील हो गयी हैं। साम्राज्यवाद विनिमय संस्कृति बढ़ने के कारण दहेज हत्याएं बढ़ गयी हैं। श्रृंगार सामग्री बेचने के लिए इस तरह का प्रचार में वृद्धि आयी कि महिलाएं सुंदर होना जरूरी है। सुंदरता की स्पर्धाएं बढ़ने के कारण महिला को बेचने की चीज के रूप में तब्दील करने की रूझान बढ़ गयी है।

दलितों पर - अधिकतर दलितों को जमीन नहीं होने के कारण वे मजदूरी कर जीने में मजबूर हैं। मुख्य रूप से इनकी जमीन समस्या हल नहीं हुई है। इन्होंने शहरी इलाकों में मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में मौजूद हैं। मानव मल को अभी भी अपनी सिर पर ढोने वाले लाखों दलितों के लिए किसी भी अधिकार नहीं होती है। आरक्षण में कटौती करना, निजीकरण में वृद्धि, नौकरी पाने की योग्यताओं में सुंदरता, आदतें और उच्च स्तर के संबंधों पर जोर देने के कारण दलितों के लिए रोजगार अवसर घट रही हैं। शिक्षा की व्यापारीकरण से उन्नत स्तर के पढ़ाई इनके लिए मुश्किल हो गयी है। इनके छात्रवृत्ति में कटौती कर रहे हैं। ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद हमले की तीव्रता इन पर ज्यादा है।

आदिवासियों पर - मोदी की शासन में आदिवासियों ने कल्याणकारी योजनाओं में तीव्र कटौती का सामना कर रहे हैं। इसकी वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई सुविधा नहीं मिलना और पौष्टिकाहार की अभाव से मामूली बीमारियों से मृत्यु हो जाना आदिवासी इलाकों में आम बात हो गयी है। मोदी सरकार ने जल-जंगल-जमीन पर अधिकार दिलाने वाली 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और पेसा कानून को आदिवासी इलाकों में लागू होने से रोक रही है। आदिवासी और गैर-आदिवासी जनता के संयुक्त संघर्ष के कारण भूमि-अधिग्रहण कानून लाने में मोदी सरकार विफल रहने के बावजूद, विकास के नाम पर लाखों आदिवासियों को जबर्दस्त विस्थापित करना देशभर में बड़े पैमाने पर जारी है। अधिकतर इलाकों में उचित मुआवजा भी इन्हें नहीं मिल रही है। घर वापसी के नाम पर हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए आदिवासियों पर हिंदू फासीवादी

हमला तीव्र रूप से जारी है।

धार्मिक अल्पसंख्यकों पर - मोदी की शासन में हिंदू पक्षपात, धार्मिक अल्पसंख्यक होने के नाते मुस्लिमों और इसाइयों पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी, भजरंग दल आदि दर्जनों संघ परिवार शक्तियों की आक्रामकता और हिंदू फासीवादी हमले में वृद्धि आयी है। विश्व आर्थिक संकट का असर देश में हिंदू धर्मोन्मद में वृद्धि के रूप में व्यक्त हो रही है। सिर्फ वर्ष 2017 में ही देशभर में मुजफ्फरपुर, सहारनपुर जैसे 822 धर्म-आधारित दंगें हुई हैं। इनमें 111 लोग मारे गए और 2,384 घायल हुए हैं।

राष्ट्रीयताओं पर - कश्मीर और उत्तर-पूर्व राष्ट्रीयताओं पर मोदी सरकार की शासन में, विशेषकर कश्मीर राष्ट्रीयता पर फासीवादी दमन अपनी चरम पर है। इन इलाकों में जनता की तीव्र विरोध का नजरअंदाज करते हुए सरकार ने सशस्त्र बलों का विशेषाधिकार कानून (अफ्स्पा) को अमल कर रही है। विशेषकर, मोदी की शासन में सरकार के भाड़े के बल सैकड़ों राष्ट्रीय क्रांतिकारियों और आम जनता को बेहद क्रूरता से हत्या और हजारों को घायल कर चुकी है। कानूनन चुने गए कश्मीर विधानसभा को रद्द करने और राष्ट्रपति शासन लगाने द्वारा कश्मीर के लिए संविधान से प्राप्त धारा 370 व धारा 35ए को मोदी सरकार ने कुचल दिया है। उत्तर-पूर्व राष्ट्रीयताओं के लोगों में राष्ट्रीय-मुक्ति आकांक्षाओं के हल के लिए मोदी सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। मणिपुर में पीएलए योद्धाओं पर भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के फासीवादी हमले जारी है। मणिपुर में झूठी मुठभेड़ों पर सुप्रीम कोर्ट में जांच करने की मांग को लेकर हुई जनांदोलन का भी 'सशस्त्र दलों की मनोबल पर चोट होने' के नाम पर मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया है। वह इसी बीच असम में चुनावों में अपनी वोट बैंक बढ़ाने की मंशा से, वहां के गैर-असमी जनता की प्रवासियों की समस्या को हल करने के नाम पर 'नागरिकता संशोधन 2016' बिल लाकर जनता के अंदर अभद्रता की स्थिति पैदा की है।

इस तरह मोदी सरकार ने मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग आदि उत्पीड़ित वर्गों, तबकों, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं को शोषण, दमन और अपमान का शिकार बनाकर दलाल नौकरशाह बुर्जुआ, बड़े सामंत वर्गों के हितों को पूरा कर लिया है। इसके खिलाफ शोषण, उत्पीड़न, दमन और अपमानों से शिकार सभी उत्पीड़ित वर्ग, तबकें, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं ने कई आंदोलनों का संचालन किए। मजदूर, किसान, छात्र-युवा, जनवादीप्रेमियों, क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों, देशभक्त, धर्मनिरपेक्ष

ताकतों, महिला, दलित, आदिवासियों, कश्मीर और उत्तर-पूर्व राष्ट्रीयताओं के आंदोलन विभिन्न स्तरों पर देशभर में हुए हैं। ये आंदोलन कई जगहों पर, कई बार जुझारू रूप ले लिए हैं। विशेषकर, कश्मीर राष्ट्रीयता ने 'आजाद' के नारे को लेकर भारतीय सेना, अर्धसैनिक और विशेष पुलिस बलों के साथ किए जा रहे साहसिक प्रतिरोध ने एक नयी नमूने को पेश किया। ये सब मोदी-अमित शाह-मोहन भागवत गुट द्वारा लागू ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के खिलाफ व्यापक जनांदोलन का रूप ले रहे हैं।

अब बाकी संसदीय पार्टियों पर नजर डालेंगे -

देश में संसदीय पार्टियों में और एक मुख्य पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी साम्राज्यवाद का दासता करते हुए, देश में अर्धऔपनिवेशिक, अर्धसामंती लुटेरी व्यवस्था को यथावत जारी रखना, 90 प्रतिशत रहे करोड़ों भारतीय उत्पीड़ित जनता का शोषण करने में अपनी खुख्यात भूमिका निभाते हुए अगली पंक्ती खड़ी है। वर्तमान चुनावों में किसी तरह अधिकार प्राप्त करने के लिए, बीते नवंबर, दिसम्बर में हुई विधानसभा चुनावों में तीन राज्यों में जिस तरह सत्ता पर अपनी कब्जा जमायी है, उसी तरह वह मुख्य रूप से बीते पांच सालों में भाजपा नेतृत्व वाली ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी एनडीए सरकार के प्रति जनता के अंदर बढ़ती तीव्र आक्रोश का इस्तेमाल करना चाहती है। वह यह कहते हुए 'जनरक्षक चेहरा' दर्शा रही है कि उत्पीड़ित जनता, तबके और राष्ट्रीयताओं पर हिंदू फासीवादी शक्तियों की हमले से सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही उन्हें बचा सकती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की पूरी इतिहास वर्तमान मोदी सरकार जैसा सभी क्षेत्रों में विफलता का ही इतिहास है; राफेल जैसे भारी घोटालों का ही इतिहास है, जीएसटी जैसे निरंकुश नीतियों को लागू करने वाला ही इतिहास है, सभी मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग आदि उत्पीड़ित वर्गों पर; महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों, इसाइयों, दलितों, आदिवासियों आदि तबकों पर; कश्मीर, उत्तर-पूर्व इलाके में असम, मणिपुरी, नागा, मिजो, बोडो, गोरखा जैसे राष्ट्रीयताओं पर फासीवादी हमले करते हुए, मानवाधिकारों और नाममात्र जनवाद का भी कुचलकर, जनवादीप्रेमियों, मानवाधिकार व सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं क्रांतिकारियों को जेलों में ठूंसने का ही इतिहास है; हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आंदोलन पर पाशविक दमन लागू करने वाला ही इतिहास है। 1984 के सिक्कों की कत्लेआम को, कांग्रेस/यूपीए की शासन में कश्मीर और उत्तर-पूर्व राष्ट्रीयताओं पर मची गयी हत्याकांड को, मुस्लिमों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं पर

अत्याचार और हत्याकांडों को देश की जनता कभी भुला नहीं जा सकती। ऐसी कांग्रेस पार्टी आज संविधान को बचाने और जनवाद को रक्षा करने के बारे में नैतिक शिक्षा दे रही है। अच्छे और बुरे हिंदुओं के बीच विभाजन करने और देश में विभिन्न संसदीय पार्टियों के साथ महागठबंधन को गठित कर चुनावों में बहुमत प्राप्त करने की सपना देख रही है। वह अच्छी तरह जानती है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में तीन राज्यों में अपनी नीतियों की खासियत से नहीं, बल्कि भाजपा के प्रति देशभर में जनता के अंदर बढ़ती तीव्र आक्रोश के वजह से ही वह जीत हासिल कर पायी है। यह तो जगजाहिर है कि जीतने के तुरंत बाद, इन राज्यों में इनकी सरकारों द्वारा नाम के वास्ते किए गए किसानों की कर्ज माफी योजना कृषि संकट तो छोड़, कम से कम किसान की कर्ज हटाने में भी किसी भी मायने में अक्षम है। दरअसल भाजपा को छोड़कर, अपने लिए वोट मांगने की कोई नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। इसलिए, हमने कांग्रेस पार्टी की साम्राज्यवाद की सेवा करने वाली दलाली वर्ग चरित्र को और उसकी जनविरोधी चरित्र को जनता के बीच भण्डाफोड़ करना चाहिए।

अब बाकी पार्टियों के बारे में देखा जाये तो, देश में नेशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ-साथ, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, आंध्रप्रदेश में तेलुगु देशम और वाइ.एस.आर. कांग्रेस, तेलंगाना में टीआरएस, तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओड़िशा और कर्नाटक में अलग-अलग पार्टियों और ग्रुपों के रूप में मौजूद जनतादल, पश्चिम बंगाल में तृणमुल कांग्रेस पार्टी, कश्मीर में नेशनल कान्फेरेंस, पीपुल्स डेमोक्रटिक पार्टी, दिल्ली में आप पार्टी, असम में असम गण परिषद, मिजोराम में मिजो नेशनल फ्रंट, छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस आदि पार्टियां मुख्य रूप में साम्राज्यवाद का ही दासता करते हुए, दलाल नौकरशाही बुर्जुआ और बड़े सामंत वर्गों का प्रतिनिधित्व वाली पार्टियां ही हैं। इनमें से अधिकतर पार्टियां विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय आकांक्षाओं का, दलित, बहुजन लोगों की मुक्ति आकांक्षाओं का इस्तेमाल करते हुए अपनी समय चला रही हैं। इसके अलावा, भाकपा (मार्क्सवादी) और भाकपा जैसी संशोधनवादी पार्टियां उत्पीड़ित जनता और तबकों के आंदोलनों को क्रांति की रास्ते से भटकाने का काम कर रही हैं। इसमें भाकपा (मार्क्सवादी) ने पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में जब सत्ता में होती है, तब जनांदोलनों को कुचलने में लगी रहती है, जब विपक्ष में होती है, तब राजनीतिक रूप से जनता की पक्ष लेने में

अवसरवादी रूख अपनाती है। यह हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने में मुख्य पार्टियों के साथ होड़ में लगी हुई है। इन सभी पार्टियां साम्राज्यवाद और लुटेरी वर्ग हितों को रक्षा करते हुए प्रतिक्रियावादी भूमिका निभा रही हैं। इसलिए, इन पार्टियों की असली वर्ग चरित्र को जहां-तहां ठोस रूप से भण्डाफोड़ करना चाहिए।

हमने चुनाव बहिष्कार अभियान में देश के संसदीय पार्टियों के वर्ग चरित्र और लोकसभा और विधानसभा चुनावों की फर्जीवाड़ा को भण्डफोड़ करने में निम्न लिखित पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए :

1. देश की 67 वर्ष का झूठी संसदीय चुनावी इतिहास में अन्याय, शोषण, उत्पीड़न और दमन के लिए आधार बने अर्धऔपनिवेशिक और अर्धसामंत सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में और उसकी राज्य-चरित्र में किसी भी तरह की बुनियादी बदलाव नहीं हुई है। उत्पीड़ित जनता के जायज बुनियादी समस्याएं हल नहीं हो पायी है। इतिहास में देखा जाये तो, वास्तव में जनता की कोई भी समस्या की समाधान जनांदोलनों, वर्गसंघर्षों और दीर्घकालीन लोकयुद्ध के जरिए ही हो पायी है, न कि संसदीय मंचों के जरिए।
2. लोकसभा और विधानसभा सिर्फ निरर्थक लफ्फाजी करने वाली जमावाड़ा क्लब (सभा) हैं। ये आरोप-प्रत्यारोप के कुत्तों के झगड़े के लिए जाना जाता है। ये करोड़ों रूपयों के टैक्स चुकाने वाली जनता के लिए बड़ा बोझ हैं। ये जनता की जीवनस्तर को बेहतर करने की नीतियां लागू नहीं कर सकते। ये हमेशा शोषक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके नियंत्रण में रहती हैं।
3. संसदीय संस्थानों और इनके लिए होने वाली चुनावों अन्य सभी सरकारी संस्थानों की तरह भारत जैसे वर्गसमाज के वर्गचरित्र से अछूत नहीं होती। ये व्यापक उत्पीड़ित जनता के हित नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह बुर्जुआ और बड़े सामंत वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधित्व वाली संस्थान कहना झूठ है।
4. सभी चुनावी पार्टियां जनता की सच्ची जनवाद, स्वावलंबन और देश की सम्प्रभुता के लिए पूरी तरह खिलाफ हैं। एक शासक पार्टी जनविरोधी

नीतियों में जब लिप्त होती है, तब इन चुनावों ने हमेशा जनता के अंदर एक विकल्प होने की भ्रम फैलाते हैं। ये एक शासक पार्टी को उससे समान होने वाली दूसरी शोषक पार्टी को विकल्प के रूप में दिखाते हैं और जनता को अपनी मुक्तिमार्ग से भटकाते हैं। एक पार्टी पर उनकी आक्रोश के कारण वही वर्ग चरित्र वाली दूसरी जनविरोधी पार्टी उसकी स्थान कब्जा कर लेती है। इस झूठी संसदीय व्यवस्था में जनता के लिए कोई विकल्प नहीं है।

5. वोटों को पैसे और शराब, धार्मिक व जातिगत भावनाओं से खरीद सकने वाली इस व्यवस्था में जनवाद के लिए जगह कहां मिलती है? अपराधियों, डाकुओं, खुख्यात भ्रष्ट राजनेताओं, धर्मोन्मदी-फासीवादी पार्टियों, साम्राज्यवादी कठपुतलियों (सभी पार्टी), घोटालेबाजों, तीन हजार सिक्कों को कत्लेआम करने वाले हत्यारों, गुजरात में दो हजार से अधिक मुस्लिमों को मौत के घाट उतार कर, वहां मानवहनन के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, अमित शाह आदि नेताओं जब चुनाव जीतते हैं, इसे जनवाद कहना हास्यास्पद है।

6. सिर्फ भारी संपदा होने वालों या अमीरों की संरक्षण होने वालों को ही चुनावों में लड़ने की अवसर मिलती है। मुख्य राजनीतिक पार्टियों में भी हाय कमांड को रिस्वत चढ़ाने वालों को ही टिकट मिलती हैं। सिर्फ मुट्ठीभर अमीरों और शक्तिमान सामंती शक्तियों और दलाल पूंजीपतियों के प्रतिनिधि ही चुनावों में लड़ सकते हैं। व्यापक जनता के लिए इन अमीर तिमिंगलों में या शासक वर्गों के प्रतिनिधियों में से किसी एक को वोट देकर चुनने का अवसर ही मिलती है। ये चुनाव अमीरों का विशेष अधिकार के रूप में तब्दील होकर, उसमें गरीबों की भूमिका पूरी तरह गायब हो गयी है।

7. हमारी देश में जनविरोधी शासन तले दबे-कुचले मजदूरों, किसानों, मध्यम वर्ग के लोगों, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, छोटे-मध्यम स्तर के देशीय पूंजीपतियों के दयनीय परिस्थितियों के लिए कांग्रेस, भाजपा, संशोधन (भाकपा और माकपा) पार्टियों और प्रांतीय पार्टियों का ही मुख्य जिम्मेदार है। इन

चुनाव मैदान में मजबूत पार्टियों और सत्ता में मौजूद लोगों ने रिगिंग (चुनावी धांधली) के जरिए धोखे से चुनाव परिणामों का पहले ही निधारित कर लेते हैं, वोटरों पर, समकक्ष प्रत्याशियों के समर्थकों पर हिंसा प्रयोग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, समकक्ष प्रत्याशियों का सफाया भी करते हैं। चुनाव बहिष्कार का आह्वान को सक्रिय रूप से लागू करने वाले क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में चुनाव पार्टियां चुनाव अधिकारियों और पुलिस वालों से सांठगांठ बनाकर रिगिंग करवाते हैं।

8. भारतीय अर्धऔपनिवेशिक और अर्धसामंत व्यवस्था में संविधान मुख्य रूप से शासक वर्गों के हितों के लिए बनायी गयी है। यही संविधान का इस्तेमाल कर शोषक-शासक वर्ग के पार्टियां अपने वर्ग हितों के लिए उत्पीड़ित जनता के आकांक्षाओं और उनके मौलिक अधिकारों को निर्दयता से कुचल देते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जनता के हितों के लिए संविधान में शामिल किसी भी अधिकार लागू नहीं होती है। संविधान ब्राह्मणीय हिंदूत्व प्रभुत्ववाली विचारधारा के अनुकूल होने के कारण वह धार्मिक अल्पसंख्यकों, उत्पीड़ित जातियों, महिलाओं और आदिवासियों के प्रति भेदभाव बरतती है। अलग होने की अधिकार सहित राष्ट्रीयताओं के लिए आत्मनिर्णय अधिकार एक जनवादी अधिकार होने के बावजूद भारतीय संविधान ने उसे कभी माना है। इसलिए देश राष्ट्रीयताओं की बंदीखाना रह गयी है। इसलिए यहां जनवादी, मानवाधिकार, क्रांतिकारी आंदोलनों और राष्ट्रीय-मुक्ति संघर्षों को केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा निर्दयता से कुचला जा रहा है।

9. जनता की समस्याओं का हल के लिए संघर्ष ही एक-मात्र रास्ता है, बल्कि चुनाव नहीं है। दलाल नौकरशाह पूंजीपति और बड़े सामंत वर्गों को और उनके साम्राज्यवादी मालिकों को उखाड़कर देशभर में जनता की क्रांतिकारी राजसत्ता को स्थापित कर, दीर्घकालीन लोकयुद्ध को अंतिम जीत की तरफ आगे बढ़ाना ही जनमुक्ति की रास्ता है।

10. चुनाव बहिष्कार जनता की जनवादी अधिकार है। साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह बुर्जुआ और बड़े सामंत वर्गों को उखाड़ कर व्यापक उत्पीड़ित जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले, उनके हितों को पूरा करने

में एक औजार के रूप में इस्तेमाल होने वाले, जनता ने खुद और पूरी तरह हिस्सा लेकर संचालित कर सकने वाली, अपने लिए निस्वार्थ और सक्षम तरीके से नेतृत्व प्रदान कर सकने वाले प्रतिनिधियों-सच्ची जनसेवकों को चुनाने में काबिल बनाने वाली नवजनवादी व्यवस्था में ही असली चुनाव हो सकती हैं।

चुनाव बहिष्कार कार्यक्रम :

☆ आज मौजूदा अर्धऔपनिवेशिक और अर्धसामंती लुटेरी व्यवस्था को यथावत जारी रखने वाली दलाल नौकरशाह बुर्जुआ और बड़े सामंत वर्ग का तानाशाह के स्थान पर जनता की सच्ची जनवादी सत्ता के लिए गारंटी देने वाली नयी लोक संविधान के बुनियाद पर निर्मित होने वाली स्वतंत्र भारतीय लोक जनतांत्रिक गणतंत्रों की संघ का गठित करने के लिए हमारी प्रयास किस तरह होती है - इसकी जानकारी देने वाली राजनीतिक कार्यक्रम को जनता के बीच जारी करना चाहिए। देश के सभी उत्पीड़ित वर्गों, सामाजिक तबकों (महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों) और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के अधिकारों के लिए नवजनवादी राज द्वारा किस तरह गारंटी दी जाती है, इसके बारे में हमने समझाना चाहिए। देश की आबादी में 90 प्रतिशत रहे मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग और देशीय बुर्जुआ वर्गों की मुक्ति के लिए क्रांतिकारी युद्ध करना जायज है, दीर्घकालीन लोकयुद्ध अनिवार्य है, इसकी समझ बढ़ाकर, उत्पीड़ित जनता के निशाने पर रहे साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह बुर्जुआ और बड़े सामंती वर्गों को उखाड़ने के लिए जारी जनयुद्ध में हिस्सा लेने जनता को आह्वानित करना चाहिए।

☆ जनता के बीच लोकसभा और विधानसभा के वर्गचरित्र, उनकी झूठी जनवादी-चरित्र के बारे में और उक्त दस पहलुओं के बारे में समझाने के लिए प्रचार टीमें बनाकर राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ पर्चे, छोटे बुकलेट, पुस्तिका और दीवार पत्रिकाओं को जारी करना चाहिए। पोस्टर और बैनर लगाना चाहिए। दीवार लेखन करना चाहिए। गाना, नुक्कड़ नाटक आडियो और वीडियो फारमेटों में माइक्रो मेमोरी कार्डों के जरिए प्रचार-प्रसार करना चाहिए। विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करना चाहिए।

☆ हमारे आंदोलन जहां मजबूत है, वहां चुनाव बहिष्कार अभियान को सक्रिय रूप से संचालित करना होगा। ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के खिलाफ, जल–जंगल–जमीन–इज्जत–अधिकार पर, जनता को विस्थापित करने वाली समझौतों (एमओयू) को रद्द करने पर, राज्यहिंसा, मनमानी तरीके से लोगों की हत्या करना, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, क्रूर ('उपा' आदि) कानूनों की समाप्ति, राफेल घोटाला, नोटबंदी, जीएसटी, किसानों की आत्महत्याएं, बेरोजगार जैसे विभिन्न समस्याओं पर, फौरी राजनीतिक समस्याओं पर हमारी दृष्टकोण के बारे में जनता के बीच स्पष्ट करना चाहिए। जहां हमारे सशस्त्र बल मौजूद नहीं है, वहां विभिन्न तरीकों से प्रचार करना चाहिए। जनता को गोलबंद कर समस्याओं को विभिन्न पार्टियों के सामने रखकर उनकी चरित्र को जनता के बीच उजागर करना चाहिए। चुनाव बहिष्कार करने वाली शक्तियों के साथ एकजुट होने के लिए प्रयास करना चाहिए।

☆ हमारा प्रचार में भाकपा और माकपा आदि संशोधनवादियों को भण्डाफोड़ करना एक मुख्य पहलू है। नेपाल के प्रचंड और भट्टाराय जैसे संशोधनवादियों को आदर्श के रूप में लेकर सत्ता में आ सकते हैं – इस तरह की प्रचार को सैद्धांतिक और राजनीतिक रूप से मुकाबला करना चाहिए।

☆ हमारे इलाकों में भाजपा और कांग्रेस पार्टियों के चुनावी सभाओं को और हमारे ऊपर आक्रामकता दर्शाने वाली मुख्य प्रांतीय पार्टियों के सभाओं को बहिष्कार करने की तरह जनता को गोलबंद करना चाहिए और बाकी पार्टियों को समस्याओं के आधार पर जनता के बीच खड़ा करना चाहिए।

☆ मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, छात्र, युवा, बुद्धिजीवी और सभी उत्पीड़ित जनता के खिलाफ साम्राज्यवादियों और ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादियों व प्रतिक्रियावादियों द्वारा संचालित 'समाधान' हमले को हराने के लिए जुझारू रूप से गोलबंद होने जनता को आह्वानित करना चाहिए।

☆ भाकपा (माओवादी) पर, क्रांतिकारी जनसंगठनों पर प्रतिबंध हटाने, 'उपा' जैसे क्रूर कानूनों को समाप्त करने, आंदोलन के इलाकों में

अर्धसैनिक बलों और कमांडो (डीआरजी जैसे प्रतिक्रांतिकारी बल और स्पेशल टॉस्क फोर्स) बलों के कैंपों को हटाने, डीआरजी, सहायक आरक्षक/एसपीओ, बस्तरिया बटालियन जैसे प्रतिक्रांतिकारी बलों को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 'अग्नि' जैसे प्रतिक्रांतिकारी संगठनों को रद्द करने और राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांगें उठानी चाहिए।

☆ वर्तमान मौजूदा विश्व आर्थिक संकटग्रस्त परिस्थितियों के लिए कारण क्या है, इसकी वजह से भारत पर क्या असर हो रहा है – इसके बारे में व्यापक रूप में प्रचार करना चाहिए। क्रांतिकारी और जनवादी आंदोलनों में जनता को व्यापक रूप से गोलबंद करना चाहिए। भारत में नवजनवादी क्रांति, उसके बाद समाजवादी क्रांति को सफल बनाने के लक्ष्य से सैद्धांतिक, राजनीतिक प्रचार व्यापक रूप से करना चाहिए।

प्रिय जनता!

हमारा देश के अर्धऔपनिवेशिक और अर्धसामंती लुटेरी व्यवस्था के स्थान पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता व मानवता-युक्त समाज अपने आप उभरकर आना संभव नहीं है। देश की पूरी संपदाओं को जिस तरह इस देश की जनता पैदा कर रहे हैं, उसी तरह शोषण और उत्पीड़नविहीन समाज का भी उन्हीं लोग अपनी आत्मगत प्रयास के जरिए निर्मित करना होगा। इस महान कार्य को कोई भी राजनीतिक पार्टी कार्यान्वित कर सकती है, इसके लिए इंतजार करना सिर्फ भ्रम ही होगा। इसलिए, इस चुनाव बहिष्कार अभियान जनता को जागरूक करने के लिए एक अच्छी अवसर के रूप में लेना चाहिए। आइए! झूठी चुनावों को बहिष्कार कर, हमारा देश में मौजूदा लुटेरी व्यवस्था को उखाड़ कर उसकी जगह सच्ची जनवाद और स्वावलंबन के बुनियाद पर भारत की जनता की जनवादी गणतत्रों की संघ का निर्माण के लिए, जोतनेवालों को जमीन के नारे लेकर, कृषि क्रांति के धुरी पर, नवजनवादी क्रांति को सफल बनाने के लक्ष्य से, सर्वहारा के नेतृत्व में, मजदूर-किसान की मित्रता के आधार पर मजदूर, किसान, निम्नपूंजीपति वर्ग, देशीय बुर्जुआ वर्गों के साथ क्रांतिकारी संयुक्तमोर्चा की बुनियाद पर जारी दीर्घकालीन लोकयुद्ध में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की तरह जनता को जागरूक करें! सिर्फ जनता की संगठित शक्ति ही चमत्कारिक परिणाम हासिल सकती है – इस सच्चाई पर उनकी समझ बढ़ाते

हुए चुनावी बहिष्कार कार्यक्रम को सफल बनाएं! जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करते हुए, जनाधार को मजबूत करते हुए, गुरिल्लायुद्ध–जनयुद्ध को बढ़ाते हुए, भारत की नवजनवादी क्रांति को आगे बढ़ाएं!

क्रांतिकारी अभिवाद के साथ

केंद्रीय कमेटी

दिनांक : 1–1–2019

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)